

**झारखंड उच्च न्यायालय, राँची****रिट याचिका (कर) सं 2795 / 2018**

हिन्दुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड (पूर्व में हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड के नाम से ज्ञात), कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निगमित कंपनी, पंजीकृत कार्यालय- यूनिलीवर हाउस, बीडी सावंत मार्ग, चकला, अंधेरी ईस्ट 400099

..... याचिकाकर्ता

**-बनाम-**

1. झारखंड राज्य, द्वारा- सचिव-सह-आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, कार्यालय- परियोजना भवन, धुरवा, डाकघर और थाना-; धुर्वा, राँची 834 004, जिला राँची

2. संयुक्त वाणिज्यिक कर आयुक्त (प्रशासन), जमशेदपुर मंडल, जमशेदपुर, डाकघर और थाना- साकची, टाउन जमशेदपुर, जिला पूर्वी सिंहभूम।

3. वाणिज्यिक कर उपायुक्त, सिंहभूम सर्कल, जमशेदपुर, डाकघर और थाना साकची, टाउन जमशेदपुर, जिला पूर्वी सिंहभूम।

..... उत्तरदाता

**कोरम: माननीय श्री न्यायमूर्ति रंगोन मुखोपाध्याय**

**माननीय श्री न्यायमूर्ति दीपक रोशन**

याचिकाकर्ता के लिए

:श्री सुमित गडोदिया, अधिवक्ता,

श्रीमती शिल्पी संदिल गडोडिया, अधिवक्ता,

श्री रंजीत कुशवाहा, अधिवक्ता

उत्तरदाता-राज्य के लिए

:श्री रत्नेश कुमार, एससी - (एल एंड सी) - 1

**विचार किया गया - 04-10-2023**

**सुनाया गया - 11/12/2023**

### निर्णय

**दीपक रोशन न्याया० द्वारा** - पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया।

2. याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित राहत के लिए प्रार्थना करते हुए तत्काल रिट आवेदन दायर किया है: -

(i) वाणिज्यिक कर अधिकरण, झारखंड, रांची द्वारा पारित दिनांक 13 अप्रैल, 2017 (अनुलग्नक-14) को रद्द करने/रद्द करने के लिए उत्प्रेषण रिट सहित एक उपयुक्त रिट/आदेश/निर्देश जारी करने के लिए। समीक्षा याचिका सं जेआर 02/2012, में दिनांक 16-12-2011 के निर्णय और आदेश (अनुबंध-9) की समीक्षा की मांग करते हुए याचिकाकर्ता द्वारा दायर आवेदन को खारिज कर दिया है।

(ii) दिनांक 16.12.2011 (अनुबंध-9) के निर्णय और आदेश को रद्द करने/रद्द करने के लिए उत्प्रेषण रिट सहित आगे उपयुक्त रिट/आदेश/निर्देश जारी करने के लिए वाणिज्यिक कर अधिकरण (संक्षेप में **अधिकरण**) द्वारा रिट याचिका सं जेआर 22/2006 में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार, याचिकाकर्ता द्वारा वनस्पति और डिटर्जेंट पाउडर की बिक्री के दूसरे बिन्दु पर कर के उद्ग्रहणीयता के संबंध में उक्त पुनरीक्षण आवेदन में उठाए गए मुद्दों को खारिज कर दिया गया है।

(iii) परमादेश रिट सहित एक और उपयुक्त रिट/आदेश/निर्देश जारी करने के लिए, उत्तरदाताओं, विशेष रूप से उत्तरदाता संख्या 3 को निर्देश देते हुए कि वे याचिकाकर्ता द्वारा सैन्य कैंटीन स्टोर विभाग को छूट प्राप्त बिक्री (लघु सीएसडी बिक्री के लिए) के संबंध में प्राप्त प्रमाण पत्र पर विचार करें, जो याचिकाकर्ता को ट्रिब्यूनल के समक्ष पुनरीक्षण कार्यवाही के चरण के दौरान प्राप्त हुआ है।

3. मामले का संक्षिप्त तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता बिहार वित्त अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के तहत एक पंजीकृत डीलर है और यह मुख्य रूप से फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स की बिक्री और विपणन के व्यवसाय में लगा हुआ है और तत्काल विवाद

निर्धारण वर्ष 2003-04 से संबंधित है, यानी 01.04.2003 से 28.01.2004 की अवधि के बीच।

4. विवाद की अवधि के दौरान, याचिकाकर्ता ने 15 जनवरी, 2004 को एक मानसा ग्रामीण और औद्योगिक विकास सोसायटी (संक्षेप में 'सोसाइटी') के साथ एक समझौता किया, जो 'डिटर्जेंट' बेचने के व्यवसाय में लगी हुई थी। समझौते के अनुसार, सोसाइटी को याचिकाकर्ता-कंपनी द्वारा निर्धारित विनिर्देश और सूत्र के अनुसार 'डिटर्जेंट' का निर्माण और पैकेजिंग करना था और याचिकाकर्ता-कंपनी को प्रश्न में उत्पादों को बेचना था। समझौते के तहत, यह विशेष रूप से प्रदान किया गया था कि याचिकाकर्ता-कंपनी पार्टियों के बीच सहमति के अनुसार उत्पाद के खरीद मूल्य का भुगतान करेगी और विक्रेता के साथ सहमत मूल्य में उत्पाद शुल्क और बिक्री कर सहित सभी कर शामिल होंगे।

मानसा ग्रामीण एवं औद्योगिक विकास समिति होने के कारण समिति को तैयार उत्पाद की बिक्री पर बिक्री कर के भुगतान से छूट का लाभ दिया गया था और उक्त तथ्य के संबंध में कोई विवाद नहीं है। विवाद की अवधि के दौरान, याचिकाकर्ता-कंपनी ने उक्त सोसायटी से 9,65,62,440/- रुपये का सामान खरीदा और चूंकि उक्त सोसाइटी द्वारा याचिकाकर्ता-कंपनी को माल की बिक्री झारखंड राज्य में बिक्री का पहला बिंदु था, इसलिए उस पर @ 12% कर लगाया गया था। तथापि, चूंकि सोसायटी को कर के भुगतान से छूट प्राप्त थी, इसलिए बिक्री के प्रथम बिन्दु पर कोई कर नहीं लगाया गया था। यह भी एक स्वीकृत तथ्य है कि बिहार वित्त अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के तहत 'डिटर्जेंट' की बिक्री केवल बिक्री के पहले बिंदु पर कर लगाने योग्य थी और किसी भी बाद की बिक्री को कर के भुगतान से छूट दी गई थी।

5. वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता ने उक्त सोसाइटी से सामान खरीदने के बाद, अपने ग्राहकों को बेच दिया और इसके बदले में, उसने दावा किया कि उक्त बिक्री को इस तथ्य के मद्देनजर छूट दी गई है कि उक्त बिक्री झारखंड राज्य में बिक्री का दूसरा बिंदु थी। हालांकि, विद्वान निर्धारण अधिकारी ने उक्त सोसायटी से खरीदे गए माल के संबंध में याचिकाकर्ता द्वारा की गई बिक्री पर छूट से इनकार कर दिया, और

01.04.2003 से 28.01.2004 की अवधि के लिए मूल्यांकन आदेश में, दिनांक 28.02.2005 को, यह निर्धारण अधिकारी द्वारा आयोजित किया गया था कि चूंकि बिक्री के पहले बिंदु को कर के भुगतान से छूट दी गई थी, इसलिए याचिकाकर्ता द्वारा की गई बिक्री, बिक्री का दूसरा बिंदु होगा, सार रूप में, झारखंड राज्य में बिक्री के पहले बिंदु के रूप में माना जाता है और, तदनुसार, @ 12% कर के लिए लगाया जाएगा। तदनुसार, याचिकाकर्ता द्वारा छूट प्राप्त बिक्री के दावे को मूल्यांकन अधिकारी द्वारा मूल्यांकन आदेश में अस्वीकार कर दिया गया था

6. इसी तरह, विवाद की अवधि के दौरान, याचिकाकर्ता ने मिहिजम वनस्पति लिमिटेड से 1,03,97,251/- रुपये के मूल्य का 'वनस्पति' खरीदा। उक्त उद्योग को भी दिनांक 04.04.1994 की छूट अधिसूचना के तहत झारखंड राज्य में बिक्री कर के भुगतान से छूट प्रदान की गई थी जो 30.03.1995 से 29.03.2005 तक वैध थी।

7. इस याचिकाकर्ता ने खाद्य तेल अर्थात् 'वनस्पति' की आपूर्ति के लिए उक्त मिहिजाम वनस्पति लिमिटेड के साथ सिद्धांत से सिद्धांत समझौता किया और उक्त उद्योग को याचिकाकर्ता के व्यापार और ब्रांड नाम में याचिकाकर्ता-कंपनी को वनस्पति का निर्माण और आपूर्ति करना आवश्यक था। याचिकाकर्ता ने उक्त वनस्पति की खरीद के बाद उसे झारखंड राज्य में बिक्री का दूसरा बिंदु होने के कारण अपने ग्राहकों को बेच दिया। बेशक, 'वनस्पति' भी बिहार वित्त अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के तहत केवल बिक्री के पहले बिंदु पर कर लगाने योग्य था और इस प्रकार, याचिकाकर्ता ने झारखंड राज्य में बिक्री का दूसरा बिंदु होने के कारण की गई बिक्री पर छूट का दावा किया। तथापि, कर निर्धारण अधिकारी ने उक्त माल की बिक्री के दूसरे बिन्दु पर याचिकाकर्ता पर कर लगाया, अन्य बातों के साथ-साथ, यह रिकार्ड करते हुए कि मिहिजम वनस्पति लिमिटेड याचिकाकर्ता के लिए जॉब वर्कर के रूप में कार्य कर रहा था और याचिकाकर्ता और मिहिजाम वनस्पति लिमिटेड के बीच बिक्री के लेन-देन को झारखंड राज्य में बिक्री का पहला बिंदु नहीं माना जा सकता है।

8. इसके अलावा, संगत निर्धारण वर्ष के दौरान, याचिकाकर्ता ने राज्य की सैन्य इकाई से संबद्ध कैंटीन स्टोर विभाग (सीएसडी) को भी बिक्री की और दिनांक 10-11-

2010 की अधिसूचना बिकरि कर/सैन/1026/77-14547 दिनांक 26 दिसंबर, 1977 के मद्देनजर बिक्री कर लगाने से छूट दी गई थी।

9. याचिकाकर्ता, पूर्वोक्त छूट अधिसूचना के संदर्भ में, इसके द्वारा की गई बिक्री की मात्रा के बारे में सैन्य कैंटीन से प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी, और, प्रासंगिक अवधि के दौरान, याचिकाकर्ता कंपनी ने सैन्य कैंटीन को 10,63,98,144/- रुपये का सामान बेचा, लेकिन केवल 9,43,48,386/- रुपये की राशि के लिए प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकता था और, तदनुसार, शेष राशि पर याचिकाकर्ता पर कर लगाया गया।

10. यह याचिकाकर्ता का मामला है कि वह बिक्री की पूरी राशि का प्रमाण पत्र पेश नहीं कर सका क्योंकि वह सेना से जुड़े कैंटीन स्टोर विभाग द्वारा जारी नहीं किया गया था, लेकिन, बाद में, याचिकाकर्ता ने 82,36,603.74 रुपये की बिक्री का प्रमाण पत्र पेश किया और इस प्रकार उक्त प्रमाण पत्र के उत्पादन पर कर की आनुपातिक कटौती का हकदार था, लेकिन इस पर विचार नहीं किया गया।

11. कर निर्धारण आदेश से व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने अपीलीय प्राधिकारी अर्थात् संयुक्त वाणिज्यिक कर आयुक्त (अपील), जमशेदपुर के समक्ष सांविधिक अपील को प्राथमिकता दी, जिसे अपील मामला संख्या एसजीएसटीए-14/2005-06 के रूप में पंजीकृत किया गया था, लेकिन याचिकाकर्ता द्वारा दायर उक्त अपील को ज्ञापन संख्या 6178 दिनांक 31.01.2006 में निहित आदेश के तहत खारिज कर दिया गया था।

तत्पश्चात्, याचिकाकर्ता ने वाणिज्यिक कर अधिकरण, झारखंड के समक्ष सांविधिक पुनरीक्षण आवेदन को प्राथमिकता दी, जिसे पुनरीक्षण याचिका सं जेआर 22/2006 के रूप में पंजीकृत किया गया था। याचिकाकर्ता द्वारा दायर पुनरीक्षण आवेदन को भी खारिज कर दिया गया था और मूल्यांकन आदेश और अपीलीय आदेश को बरकरार रखा गया था और 'वनस्पति' और 'डिटर्जेंट' की बिक्री के दूसरे बिंदु के संबंध में याचिकाकर्ता पर कर की देयता को बरकरार रखा गया था। इसके अलावा, पुनरीक्षण कार्यवाही के दौरान, हालांकि याचिकाकर्ता ने 82,36,603.74/- रुपये के मूल्य की सीएसडी बिक्री की छूट का दावा करने के लिए प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया, लेकिन

उक्त प्रमाण पत्र पर पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा विचार नहीं किया गया। पुनरीक्षण प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता के पुनरीक्षण आवेदन को खारिज करते हुए, याचिकाकर्ता द्वारा उपरोक्त दो संस्थाओं के साथ किए गए समझौतों की वैधता और विश्वसनीयता के प्रश्न पर विचार किया और यह माना कि उक्त समझौते भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 23 के प्रावधानों के विपरीत हैं, क्योंकि उक्त समझौते याचिकाकर्ता द्वारा केवल छूट के लाभ या कर के भुगतान से बचने के इरादे से एक नया उद्योग का दावा करने के लिए किए गए हैं जो उपरोक्त सोसायटी को दिया गया था।

**12.** याचिकाकर्ता, वाणिज्यिक कर न्यायाधिकरण, झारखंड द्वारा दिए गए निष्कर्षों से व्यथित होकर, उक्त ट्रिब्यूनल के समक्ष एक समीक्षा याचिका दायर की जिसे समीक्षा याचिका संख्या जेआर 02/2012 के रूप में पंजीकृत किया गया था। समीक्षा याचिका में, याचिकाकर्ता ने ट्रिब्यूनल के ध्यान में लाया कि 29.01.2004 से 31.03.2004 की अवधि के लिए उसी विवाद के संबंध में, निर्धारण अधिकारी ने इसी तरह का आदेश पारित किया था जिसमें कहा गया था कि याचिकाकर्ता छूट प्राप्त इकाइयों से खरीदे गए डिटर्जेंट और वनस्पति की बिक्री के दूसरे बिंदु पर छूट के लिए हकदार नहीं था। उक्त अवधि के संबंध में, याचिकाकर्ता ने संयुक्त वाणिज्यिक कर आयुक्त (अपील), जमशेदपुर के समक्ष अपील दायर की और विद्वान अपीलकर्ता न्यायालय ने दिनांक 23.08.2008 के आदेश के तहत उक्त अपील की अनुमति दी और मामले को वापस कर निर्धारण अधिकारी को भेज दिया। अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित रिमांड आदेश पर कर निर्धारण अधिकारी ने दिनांक 11-12-2008 के संशोधित कर निर्धारण आदेश के तहत याचिकाकर्ता द्वारा की गई बिक्री को झारखंड राज्य में बिक्री का दूसरा बिन्दु होने के कारण छूट प्राप्त बिक्री के रूप में माना। बाद की अवधि के लिए समान पक्षों के बीच एक ही विवाद के संबंध में ट्रिब्यूनल के ध्यान में लाए जाने के बावजूद, जिसमें झारखंड राज्य में बिक्री का दूसरा बिंदु होने के लिए याचिकाकर्ता के दावे को मूल्यांकन अधिकारी द्वारा अनुमति दी गई थी, याचिकाकर्ता द्वारा दायर समीक्षा याचिका को ट्रिब्यूनल द्वारा निर्णय और आदेश दिनांक 13 अप्रैल 2017 के माध्यम से खारिज कर दिया गया था।

13. समीक्षा याचिका को खारिज करते हुए, ट्रिब्यूनल द्वारा एक और निष्कर्ष दिया गया था कि दोनों उद्योगों ने छूट अधिसूचना के अनुसार याचिकाकर्ता को बिक्री नहीं दिखाई है। ट्रिब्यूनल का यह निष्कर्ष रिकॉर्ड से बाहर नहीं था, क्योंकि यह एक निर्विवाद तथ्य था कि याचिकाकर्ता ने उपरोक्त दो संस्थाओं यानी मानसा रूरल एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सोसाइटी और मिहिजम वनस्पति लिमिटेड से सामान खरीदा था।

14. ट्रिब्यूनल द्वारा पारित पूर्वोक्त निर्णय से व्यथित होकर, याचिकाकर्ता द्वारा वर्तमान रिट आवेदन दायर किया गया है।

15. तत्काल रिट आवेदन को पहले इस न्यायालय द्वारा विचार के लिए लिया गया था और 21 दिसंबर, 2018 के आदेश के तहत, रिट याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया गया था और इस न्यायालय द्वारा एक विस्तृत अंतरिम आदेश पारित किया गया था, जिसमें याचिकाकर्ता पर लगाए गए कर के लिए 50.00 लाख रुपये जमा करने की शर्त के अधीन आक्षेपित मांग पर रोक लगा दी गई थी। तैयार संदर्भ के लिए, इस न्यायालय द्वारा पारित 21 दिसंबर, 2018 को पारित अंतरिम आदेश यहां उद्धृत किया गया है: -

**"अंतर्वर्ती आवेदन सं.5071/ 2018"**

4. इस अंतर्वर्ती आवेदन को वाणिज्यिक कर अधिकरण, रांची द्वारा दिनांक 16 दिसंबर, 2011 को पुनरीक्षण याचिका में पारित आदेश के संचालन, कार्यान्वयन और निष्पादन पर रोक लगाने के लिए प्राथमिकता दी गई है। पुनरीक्षण याचिका सं जेआर 22/2006 (इस रिट याचिका के ज्ञापन के अनुबंध-9) के साथ-साथ वाणिज्यिक कर अधिकरण, रांची द्वारा पुनरीक्षण याचिका जेआर 02/2012 दिनांक 13 अप्रैल, 2017 (इस रिट याचिका के ज्ञापन के अनुलग्नक-14) में पारित आदेश के प्रचालन, कार्यान्वयन और निष्पादन के विरुद्ध स्थगन प्राप्त करने के लिए।

5. दोनों पक्षों के विद्वान वकीलों को सुनने और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखने के बाद, ऐसा प्रतीत होता है कि इस याचिकाकर्ता के पक्ष में मुख्य रूप से इस कारण से एक प्रथम दृष्टया मामला है कि बिहार वित्त अधिनियम, 1981 के तहत कर देयता बिक्री के पहले बिंदु पर

थी। बिक्री के पहले बिंदु को सरकार द्वारा एसओ संख्या 96 दिनांक 4 अप्रैल, 1994 के परिपत्र के तहत छूट दी गई है। यह याचिकाकर्ता दो आइटम खरीद रहा है: -

(क) डिटर्जेंट; और

(ख) वनस्पति तेल

डिटर्जेंट मनसा ग्रामीण एवं औद्योगिक विकास सोसायटी से खरीदे जा रहे हैं और वनस्पति ऑयल मिहिजम वनस्पति लिमिटेड से खरीदे जा रहे हैं। इन दोनों कंपनियों के बीच बिक्री और इस याचिकाकर्ता को परिपत्र सं एसओ 96 और एसओ 239 दिनांक 1 जून, 1996 दिनांक 4 अप्रैल, 1994 के अनुसार छूट प्राप्त है। ऐसा एक परिपत्र प्रतिवादियों द्वारा दायर जवाबी हलफनामे के अनुलग्नक-डी में है। बिक्री के पहले बिंदु पर, कर एकत्र किया जाना है और अब इसे छूट दी गई है, इसलिए इस याचिकाकर्ता और उपभोक्ताओं के बीच दूसरी बिक्री कर योग्य नहीं है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को देखते हुए (1998) 5 8 एससीसी 349 विशेष रूप से अनुच्छेद 9 को अनुच्छेद 13 और 14 के साथ पढ़ा जाना है।

6. उपरोक्त तथ्यों और न्यायिक निर्णय के मद्देनजर, इस याचिकाकर्ता के पक्ष में प्रथम दृष्टया से अधिक मामला है, सुविधा का संतुलन भी इस याचिकाकर्ता के पक्ष में है और यदि स्थगन, जैसा कि प्रार्थना की गई है, नहीं दी जाती है, तो यह इस याचिकाकर्ता को अपूरणीय क्षति पहुंचाएगा। अतः हम वाणिज्यिक कर अधिकरण, रांची द्वारा दिनांक 16 दिसम्बर, 2011 को पुनरीक्षण याचिका सं जेआर 22/2006 (इस रिट याचिका के ज्ञापन के अनुबंध-9) में पारित आदेश के प्रचालन, कार्यान्वयन और निष्पादन पर रोक लगाते हैं। इसके साथ-साथ वाणिज्यिक कर अधिकरण, रांची द्वारा पुनरीक्षण याचिका सं जेआर 02/2012 दिनांक 13 अप्रैल, 2017 (इस रिट याचिका के ज्ञापन के अनुलग्नक-14) में पारित आदेश के प्रचालन, कार्यान्वयन और निष्पादन पर रोक लगा दी है, इस रिट याचिका की लंबित और अंतिम सुनवाई के दौरान, इस शर्त पर कि यह याचिकाकर्ता आज से छह सप्ताह की अवधि के भीतर उत्तरदाताओं के पास 50 लाख रुपये जमा करेगा। इस राशि को उत्तरदाताओं के पास जमा राशि के रूप में

माना जाएगा। न तो, इस याचिकाकर्ता द्वारा इस राशि का भुगतान और न ही उत्तरदाताओं द्वारा इस राशि की प्राप्ति को किसी भी तथ्य की स्वीकारोक्ति माना जाएगा। यह राशि इस याचिका से उत्पन्न होने वाली किसी भी दायित्व, यदि कोई हो, के प्रति रिट याचिका के अंतिम निर्णय के समय एक सेट-ऑफ के रूप में दी जाएगी

7. इसलिए, 2018 का अंतर्वर्ती आवेदन संख्या 5071 की अनुमति दी जाती है और उसका निपटान किया जाता है।

**अंतर्वर्ती आवेदन नंबर 11040/2018**

8. इस अंतर्वर्ती आवेदन को उत्तरदाताओं द्वारा इस याचिकाकर्ता को 30 नवंबर, 2018 को दिए गए संचार के संचालन, कार्यान्वयन और निष्पादन के खिलाफ रोक लगाने के लिए प्राथमिकता दी गई है, जो इस अंतर्वर्ती आवेदन के ज्ञापन के अनुलग्नक- आई. ए-1 में है।

9. दोनों पक्षों के वकीलों को सुनने और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखने और इस रिट याचिका में अंतर्वर्ती आवेदन संख्या 5071/2018 में आज पारित आदेश को देखने के बाद, परिणामस्वरूप 30 नवंबर, 2018 का आदेश/संचार जो इस अंतर्वर्ती आवेदन के ज्ञापन के अनुलग्नक- आई. ए-1 में है, एतद्वारा, इस रिट याचिका के लंबित रहने और अंतिम सुनवाई के दौरान भी रोक लगा दी गई। चूंकि 50 लाख रुपये की शर्त पहले ही लगाई जा चुकी है, इसलिए इस याचिकाकर्ता के पक्ष में प्रथम दृष्टया से अधिक मामले होने के कारण स्थगन देने के लिए कोई और शर्त लगाने की आवश्यकता नहीं है, सुविधा का संतुलन भी इस याचिकाकर्ता के पक्ष में है और यदि स्थगन, जैसा कि प्रार्थना की गई है, नहीं दी जाती है, तो यह इस याचिकाकर्ता को अपूरणीय क्षति पहुंचाएगा।

10. अंतर्वर्ती आवेदन संख्या 11040/2018, इसलिए, अनुमति दी जाती है और निपटाया जाता है।”

16. श्री सुमित गडोडिया, एडवोकेट, श्रीमती शिल्पी संदिल गडोडिया की सहायता से, बिक्री के दूसरे बिंदु पर कर लगाने के आक्षेपित निर्णय पर हमला किया है, इस तथ्य के बावजूद कि 'डिटर्जेंट' और 'वनस्पति' तेल झारखंड राज्य में बिक्री के पहले बिंदु पर कर योग्य थे, अन्य बातों के साथ, यह तर्क देते हुए कि केवल इसलिए कि

याचिकाकर्ता ने छूट प्राप्त उद्योगों से माल खरीदा था और, तत्पश्चात्, झारखंड राज्य में बिक्री का दूसरा बिन्दु होने के कारण बिक्री के दूसरे बिन्दु के लेन-देन को बिक्री के प्रथम केन्द्र पर कराधेय नहीं माना जा सकता है।

17. यह प्रस्तुत किया गया है कि जब माल, जो बिक्री के पहले बिंदु पर कर के अधीन हैं, छूट दी जाती है, तो बिक्री के दूसरे बिंदु पर कर के किसी भी बाद के लेवी एकल चरण कर का उल्लंघन होगा. यह तर्क दिया गया है कि कर से छूट का लाभ देने का अर्थ यह नहीं है कि माल पर कर बिल्कुल नहीं लगाया गया था, लेकिन यह तर्क दिया गया था कि छूट को ध्यान में रखते हुए लगाया जाने वाला कर शून्य था और चूंकि कर का प्रभाव केवल बिक्री के पहले बिंदु पर था, इसलिए इसे बाद के चरण में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। पूर्वोक्त तर्क के समर्थन में, याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा किया है, अर्थात्-

(i) शनमुगा ट्रेडर्स आदि बनाम तमिलनाडु राज्य एवं अन्य के मामले (1999) एसटीसी 1 (एससी); (1998) 5 एससीसी 349 में रिपोर्ट की गई

(ii) पीके री-रोलिंग मिल्स (प्रा) लि बनाम सहायक आयुक्त एवं अन्य, (2007) 4 एससीसी 30 में रिपोर्ट किया गया;

(iii) आइरिस इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड v. बनाम बिहार राज्य एवं अन्य (2003) 132 एसटीसी 185 में रिपोर्ट किया गया;

18. यह आगे तर्क दिया गया है कि विद्वान ट्रिब्यूनल द्वारा दिया गया निष्कर्ष कि याचिकाकर्ता द्वारा उपरोक्त दो संस्थाओं के साथ दर्ज किए गए अनुबंध भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 23 का उल्लंघन थे, पूरी तरह से विकृत और मामले के रिकॉर्ड से परे है। यह प्रस्तुत किया गया है कि एक इकाई कानून के अनुसार अपनी कर योजना बनाने का हकदार है, और, केवल इसलिए कि याचिकाकर्ता ने एक इकाई होने के नाते छूट प्राप्त इकाई से बिक्री के पहले बिंदु पर उगाही योग्य सामान खरीदा है, अनुबंध को भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 23 का उल्लंघन नहीं करेगा।

19. यह आगे तर्क दिया गया है कि ट्रिब्यूनल ने एक विकृत निष्कर्ष दिया है कि उपरोक्त दो संस्थाओं ने याचिकाकर्ता को किए गए सामानों की बिक्री नहीं दिखाई है। इस संबंध में, याचिकाकर्ता ने रिट आवेदन के अनुलग्नक -10 पर भरोसा किया है, जिसमें चालान, रोड परमिट आदि वाली पुस्तिकाओं का विवरण शामिल है, जो याचिकाकर्ता द्वारा ट्रिब्यूनल के समक्ष प्रस्तुत किया गया था ताकि इस तथ्य को प्रदर्शित किया जा सके कि याचिकाकर्ता ने वास्तव में उपरोक्त दो संस्थाओं से बिक्री के लेनदेन के माध्यम से सामान खरीदा और उसके बाद, अपने ग्राहकों को सामान बेच दिया। यह जोरदार तर्क दिया गया है कि ट्रिब्यूनल ने यह निष्कर्ष देकर मूल्यांकन आदेश और अपीलीय आदेश से परे यात्रा की है कि उपरोक्त दो संस्थाओं ने याचिकाकर्ता को माल भी नहीं बेचा है, जो राजस्व का मामला भी नहीं था। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि किसी भी समय, निर्धारण अधिकारी और/या अपीलीय प्राधिकारी ने इस तथ्य पर विवाद नहीं किया है कि याचिकाकर्ता ने उपरोक्त दो संस्थाओं से बिक्री लेनदेन के माध्यम से सामान खरीदा था और मूल्यांकन अधिकारी द्वारा उठाया गया एकमात्र विवाद यह था कि 'क्या बिक्री जिसे कर के भुगतान से छूट दी गई थी, उसे बिक्री के पहले बिंदु के रूप में माना जा सकता है' और यह घोषित करने के बाद कि छूट प्राप्त बिक्री की बिक्री माल को बिक्री के पहले 10 बिंदु के रूप में नहीं माना जाएगा, याचिकाकर्ता पर कर उसके द्वारा अपने ग्राहकों को किए गए सामानों की बिक्री के दूसरे बिंदु पर लगाया गया था।

20. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने 29.01.2004 से 31.03.2004 की अवधि के लिए संयुक्त वाणिज्यिक कर आयुक्त (अपील), जमशेदपुर द्वारा पारित दिनांक 23.08.2008 के आदेश की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया, जिसमें अपीलीय प्राधिकारी ने ठीक इसी मुद्दे पर मामले को नए सिरे से निर्णय के लिए मूल्यांकन अधिकारी को भेज दिया है।

21. विद्वान अधिवक्ता ने 11 दिसंबर, 2008 के संशोधित मूल्यांकन आदेश को हमारे ध्यान में लाया और यह प्रदर्शित किया है कि अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित रिमांड आदेश पर मूल्यांकन अधिकारी ने याचिकाकर्ता द्वारा अपने ग्राहकों को की गई बिक्री के दूसरे बिंदु को छूट प्राप्त बिक्री के रूप में माना है। उपरोक्त के आधार पर,

यह तर्क दिया गया है कि कर अधिकारियों ने स्वयं बाद की अवधि के लिए, याचिकाकर्ता द्वारा की गई दूसरी बिक्री को छूट प्राप्त बिक्री के रूप में माना है, और, कर अधिकारियों के उक्त निष्कर्ष को झारखंड राज्य द्वारा किसी भी मंच के समक्ष चुनौती नहीं दी गई है। इस संबंध में याचिकाकर्ता द्वारा 'गोदरेज सारा ली लिमिटेड बनाम आबकारी और कराधान अधिकारी-सह-निर्धारण प्राधिकरण और अन्य' के मामले में भरोसा किया गया था, जिसकी रिपोर्ट (2023) (अनुच्छेद 34 और 35) एससीसी ऑनलाइन एससी 95 में की गई थी। । जिसमें यह माना गया है कि एक बार जब निर्णय को विभाग द्वारा चुनौती नहीं दी जाती है, तो विभाग द्वारा इसका पालन किया जाना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय **भारत संचार निगम लिमिटेड और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य (2006) 3 एससीसी 1 (अनुच्छेद-20)** के मामले में विधि के पूर्वोक्त प्रस्ताव पर मैं रिपोर्ट किया गया।

22. श्री रत्नेश कुमार, राज्य के लिए विद्वान अधिवक्ता, इसके विपरीत, आक्षेपित आदेश का बचाव किया है और यह प्रस्तुत किया गया है कि, स्वीकार्य रूप से, विचाराधीन सामान याचिकाकर्ता द्वारा इकाइयों से खरीदे गए थे, जिन्हें कर लगाने के पहले बिंदु पर कर के भुगतान से छूट दी गई थी। यह प्रस्तुत किया गया है कि कर राशि के अनुसार कर राशि एकत्र नहीं करना अनिवार्य रूप से तात्पर्य है कि शुरू करने के लिए कभी कोई लेवी नहीं थी, और चूंकि कर की कोई लेवी नहीं थी, इसलिए याचिकाकर्ता द्वारा अपने ग्राहकों को की गई बिक्री को झारखंड राज्य में पहली बिक्री माना जाएगा।

जोरदार ढंग से यह प्रस्तुत किया गया है कि *डिटर्जेंट* और *वनस्पति* पर कर लगाने का प्रावधान बिक्री के पहले बिंदु पर किया गया है न कि कराधेय बिक्री के पहले बिंदु पर, और, चूंकि बिक्री का पहला बिंदु स्वयं कर योग्य नहीं था, बाद की बिक्री को कानून के तहत बिक्री का पहला बिंदु माना जाएगा। आगे यह तर्क दिया गया है कि दायित्व की वसूली के अभाव में और चूंकि बिक्री के पहले बिंदु पर कर का कोई संग्रह नहीं हुआ है, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि विचाराधीन माल झारखंड राज्य द्वारा एकत्र किए जा रहे कर पर लगाया गया है और, तदनुसार, जब वही माल बिक्री

के दूसरे बिंदु पर बेचा गया था, कर निर्धारण अधिकारी ने बिक्री के दूसरे बिंदु पर सही कर लगाया है।

23. इसके अलावा, ट्रिब्यूनल द्वारा दिए गए निष्कर्ष के संबंध में कि प्रश्न में समझौते भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 23 का उल्लंघन करने के कारण शून्य थे, यह प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता ने जानबूझकर ऐसी इकाइयों के साथ समझौतों में प्रवेश किया जिन्हें कर के भुगतान से छूट दी गई थी, कर देयता से बचने के लिए और उक्त संस्थाओं से माल खरीदा है, यह अच्छी तरह से जानते हुए कि कर पर लगाया जाएगा बिक्री का पहला बिंदु जिसे छूट दी गई है। इसलिए, यह तर्क दिया गया था कि ट्रिब्यूनल द्वारा दिया गया निष्कर्ष कि समझौते भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 23 का उल्लंघन करते हुए शून्य हैं, पूरी तरह से उचित है।

24. कैंटीन की बिक्री और याचिकाकर्ता द्वारा 82,36,603.74/- रुपये की राशि के अतिरिक्त प्रमाण पत्र के उत्पादन के संबंध में, उत्तरदाताओं की ओर से यह उचित रूप से प्रस्तुत किया गया है कि यदि उक्त अतिरिक्त प्रमाण पत्र याचिकाकर्ता के कब्जे में है, तो उसे मूल्यांकन प्राधिकारी के समक्ष पेश किया जा सकता है और इसका लाभ याचिकाकर्ता को मूल्यांकन प्राधिकरण द्वारा दिया जाएगा।

25. हमने पार्टियों के प्रतिद्वंद्वी तर्कों पर विचार किया है और दलीलों के माध्यम से देखा है और, हमारी राय में, तत्काल रिट आवेदन में, इस न्यायालय द्वारा निर्धारण के लिए निम्नलिखित दो मुद्दे शामिल हैं, अर्थात्;

- (1) क्या याचिकाकर्ता पर वनस्पति और डिटर्जेंट की बिक्री के दूसरे बिंदु पर कर लगाया जा सकता है, जिसे उसके द्वारा एक छूट प्राप्त सोसाइटी/उद्योग से खरीदा गया था?
- (2) क्या याचिकाकर्ता कैंटीन स्टोर विभाग (सीएसडी), रामगढ़ कैंट से प्राप्त प्रमाण पत्र पर विचार करने का हकदार है? जो याचिकाकर्ता को बिक्री राशि पर छूट का दावा करने का हकदार होगा, क्योंकि सीएसडी को बिक्री कर के भुगतान से छूट दी गई थी।

26. मुद्दा संख्या 1: तत्काल रिट आवेदन में निर्णय के लिए शामिल यह मुद्दा अब एकीकृत नहीं है और **शनमुगा ट्रेडर्स (सुप्रा)** और **पीके री-रोलिंग मिल्स (पी) लिमिटेड**

(सुप्रा) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों द्वारा पहले ही सुलझाया जा चुका है। यह एक स्वीकृत तथ्य है कि याचिकाकर्ता ने मनसा ग्रामीण एवं औद्योगिक विकास सोसाइटी से सामान खरीदा है, जो सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत सोसायटी है। दिनांक 1 जून, 1996 की एसओ 237 के अनुसार बिहार राज्य खादी गामोद्योग बोर्ड/खादी एवं गामोद्योग आयोग के स्वामित्व वाली विनिर्माण इकाई अथवा समिति पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत सहकारी समितियों और संस्थाओं द्वारा की गई बिक्री को कर के उद्ग्रहण से छूट दी गई थी। उक्त अधिसूचना में शौचालय, शौचालय साबुन और डिटर्जेंट पाउडर को शामिल किया गया था जिन्हें कर से छूट दी गई थी यदि सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत सहकारी समिति द्वारा निर्मित इकाई द्वारा विनिर्मित किया जाता है। इसलिए, यह एक निर्विवाद तथ्य है कि मानसा ग्रामीण एवं औद्योगिक विकास सोसाइटी ऑफ डिटर्जेंट पाउडर, जो झारखंड राज्य में बिक्री का पहला बिंदु है, द्वारा की गई बिक्री को कर के भुगतान से छूट दी गई थी।

27. इसी प्रकार, यह एक स्वीकृत तथ्य है कि मिहिजाम वनस्पति लिमिटेड द्वारा खाद्य तेल अर्थात् 'वनस्पति' की बिक्री को दिनांक 04.04.1994 की छूट अधिसूचना के मद्देनजर कर के भुगतान से छूट दी गई थी जो 30.03.1995 से 29.03.2005 तक वैध थी।

28. याचिकाकर्ता ने उपरोक्त दो संस्थाओं से डिटर्जेंट पाउडर और वनस्पति तेल खरीदा, जिन्हें कर के भुगतान से छूट दी गई थी। यह भी एक स्वीकृत तथ्य है कि उपर्युक्त माल नामत डिटर्जेंट पाउडर और वनस्पति पर कर के केवल एक बिंदु अर्थात् झारखंड राज्य में पहली बिक्री पर ही कर लगाया गया था।

29. पूर्वोक्त तथ्यों के मद्देनजर, इस न्यायालय द्वारा विचार के लिए प्रश्न उठता है कि "क्या माल, जो कर के एकल बिंदु पर कर के लिए लगाए गए थे, अर्थात्, पहली बिक्री, लेकिन कर के उद्ग्रहण से छूट दी गई थी, उक्त बिक्री को पहली बिक्री मानकर बिक्री के दूसरे बिंदु पर कर लगाने के अधीन किया जा सकता है?"

30. जैसा कि पहले ही ऊपर कहा गया है, पूर्वोक्त मुद्दा अब एकीकृत नहीं है और शनमुगा ट्रेडर्स (सुप्रा) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने फैसले में पहले ही तय किया जा चुका है। उक्त मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 14 और 15 पर विचार कर रहा था जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि विशेष महत्व की घोषित वस्तुओं पर केवल एक ही स्तर पर कर लगाया जाएगा। उक्त मामले में, तमिलनाडु राज्य ने एक परिपत्र जारी किया है जिसमें बिक्री के एक से अधिक चरणों में घोषित माल पर इस आधार पर कर लगाने का प्रावधान है कि उक्त घोषित माल की बिक्री के प्रथम चरण में कोई कर नहीं लगाया गया था क्योंकि कर लगाने पर छूट का प्रावधान किया गया था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उपर्युक्त निर्णय में स्पष्ट रूप से निर्णय दिया कि केवल इसलिए कि राज्य में पहली बिक्री को छूट दी गई है, बाद में राज्य में बिक्री पर कर नहीं लगेगा। पूर्वोक्त निर्णय के अनुच्छेद 12, 13 और 14 को उद्धृत करना लाभदायक होगा, जो निम्नानुसार है: -

*"12. हमें नहीं लगता कि अपील के तहत आदेश में मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा निष्कर्ष को बरकरार रखा जा सकता है। जिन वस्तुओं से हमारा संबंध है, उन्हें माल घोषित किया जा रहा है, उन पर केवल एक बिंदु पर कर लगाया जा सकता है, अर्थात् राज्य में केवल एक बिक्री पर कर लगाया जा सकता है। यह निर्धारित करना राज्य का काम है कि क्या एक बिंदु राज्य में पहली बिक्री का बिंदु होना चाहिए या राज्य में अंतिम बिक्री या राज्य में कोई मध्यवर्ती बिक्री होनी चाहिए। यदि एकल बिंदु राज्य द्वारा निर्धारित किया जाता है, तो कहते हैं, पहली बिक्री का बिंदु और राज्य पहली बिक्री को कर के भुगतान से छूट देता है, या तो एक सामान्य प्रावधान या विक्रेता के एक वर्ग पर लागू एक विशिष्ट प्रावधान द्वारा, विशेष विक्रेता या बेची गई वस्तुओं को राज्य में पहली बिक्री या किसी भी बाद की बिक्री के बिंदु पर कर के अधीन नहीं किया जा सकता है।"*

*13. राज्य अधिनियम की दूसरी अनुसूची एकल बिंदु निर्दिष्ट करती है; यह "राज्य में पहली बिक्री का बिंदु" है। राज्य में पहली बिक्री उक्त बोर्ड द्वारा अपीलकर्ताओं/याचिकाकर्ताओं को की गई बिक्री थी। उस बिक्री को उपर्युक्त दिनांक 1.12.1982 की अधिसूचना के कारण कर से छूट दी गई थी। इसलिए, उक्त बोर्ड*

द्वारा अपीलकर्ताओं/याचिकाकर्ताओं को बेचा गया लोहा और इस्पात राज्य में पहली बिक्री या बाद में किसी बिक्री के बिंदु पर कर के लिए उत्तरदायी नहीं था।

14. जोर है कि वाक्यांश "कर योग्य बिक्री" पर मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा रखा गया है प्रतीत होता है के लिए कोई वारंट नहीं है। राज्य अधिनियम पहली कर योग्य बिक्री पर लेवी के एकल बिंदु को ठीक नहीं करता है; यह इसे "पहली बिक्री के बिंदु" पर ठीक करता है। आक्षेपित परिपत्र वैध रूप से पहली बिक्री से बाद की बिक्री के लिए लेवी के बिंदु को स्थानांतरित नहीं कर सकता है और इसलिए, यह कानून में गलत है।

31. पूर्वोक्त निर्णय के अवलोकन से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से माना है कि यदि किसी भी माल की बिक्री पर राज्य द्वारा एक बिंदु तय किया जाता है और बिक्री को कर के भुगतान से छूट दी जाती है, तो बाद में बिक्री राज्य द्वारा कर के लिए नहीं होगी। हमारी राय में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का उपरोक्त निर्णय वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर पूरी तरह से लागू होता है और याचिकाकर्ता का मामला पूर्वोक्त निर्णय द्वारा पूरी तरह से कवर किया गया है।

32. *शनमुगा ट्रेडर्स* के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का *पीके री-रोलिंग मिल्स (पी) लिमिटेड (सुप्रा)* के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुसरण किया गया। उक्त मामले में भी उठाया गया प्रश्न केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के अंतर्गत घोषित माल पर बिक्री के एक से अधिक चरणों में कर लगाने के संबंध में था। उक्त मामले में भी, राज्य के अधिवक्ता 14 ने प्रतिवादियों के अधिवक्ता द्वारा तत्काल मामले में दिए गए तर्कों के समान तर्क दिए कि किसी भी संग्रह के अभाव में, कर की कोई लेवी या देयता नहीं होगी और तदनुसार, दूसरी बिक्री पर कर लगाया जाएगा। उत्तरदाताओं द्वारा दिए गए उक्त तर्क को विशेष रूप से माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया था और यह स्पष्ट रूप से माना गया था कि संग्रह और लेवी दो अलग-अलग चीजें हैं और यह संग्रह लेवी का एक अनिवार्य पहलू नहीं है। उक्त मामले में, यह आगे कहा गया है कि छूट के बावजूद, कर का दायित्व अप्रभावित रहता है और छूट के माध्यम से, देयता को पूरा करने के लिए

कर के भुगतान की केवल बाद की आवश्यकता को समाप्त किया जाता है। संक्षेप में, यह माना गया था कि छूट देयता को शून्य नहीं करती है, लेकिन केवल कर के भुगतान की देयता को पूरा करने की आवश्यकता को समाप्त करती है।

33. हमारी राय है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त दो निर्णय वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर पूरी तरह से लागू होते हैं, और, केवल इसलिए कि याचिकाकर्ता ने छूट प्राप्त इकाइयों से झारखंड राज्य में बिक्री के पहले बिंदु पर कर योग्य माल खरीदा है, याचिकाकर्ता द्वारा अपने ग्राहकों को की गई बिक्री को झारखंड राज्य में पहली बिक्री के रूप में नहीं माना जाएगा।

34. इस स्तर पर, हम मामले के एक और पहलू को उजागर करना चाहेंगे जिस पर याचिकाकर्ता ने तर्क दिया है। यह हमारे ध्यान में लाया गया था कि वर्तमान विवाद 01.04.2003 से 28.01.2004 की अवधि से संबंधित है, और, बाद की अवधि के लिए, याचिकाकर्ता के मूल्यांकन प्राधिकारी ने स्वयं इस तथ्य को स्वीकार किया कि याचिकाकर्ता द्वारा अपने ग्राहकों को की गई दूसरी बिक्री कर के लिए नहीं होगी, इस तथ्य के बावजूद कि पहली बिक्री जिसके द्वारा याचिकाकर्ता ने माल खरीदा है, कर की देयता से मुक्त था। यह एक स्वीकृत तथ्य है कि निर्धारण अधिकारी के पूर्वोक्त निर्णय को विभाग द्वारा उच्च मंच के समक्ष चुनौती नहीं दी गई थी और इस प्रकार, बाद की अवधि के लिए, याचिकाकर्ता को छूट का लाभ दिया गया है।

35. श्री रत्नेश कुमार, राज्य के लिए विद्वान अधिवक्ता वहाँ कर कानून में कोई पुनःन्याय है और प्रत्येक आकलन वर्ष एक कर कानून में अलग होने के लिए माना जाता है कि प्रस्ताव पर निर्भरता रखकर आकलन अधिकारी के पूर्वोक्त बाद के निर्णय भेद करने की कोशिश की है। राज्य के अधिवक्ता द्वारा उठाए गए पूर्वोक्त प्रस्ताव में कोई विवाद नहीं है कि पुनःन्याय अलग-अलग निर्धारण वर्ष के लिए कर से संबंधित मामले में लागू नहीं होता है, क्योंकि रेस जुडिकाटा कार्रवाई के एक ही कारण पर मनोरंजक मुद्दे से अदालतों पर लागू होता है, जबकि प्रत्येक मूल्यांकन वर्ष के लिए कार्रवाई का कारण अलग है।

हालांकि, विभिन्न निर्धारण वर्षों से संबंधित कर मामलों में पुनर्निर्णय लागू नहीं है, यह भारत संचार निगम लिमिटेड (सुप्रा) के मामले में दिए गए अपने निर्णय सहित अपने विभिन्न निर्णयों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बार-बार आयोजित किया गया है कि; जहां बाद के निर्धारण वर्ष में तथ्य और कानून समान हैं, किसी भी प्राधिकरण, चाहे वह अर्ध-न्यायिक हो या न्यायिक, को आम तौर पर एक अलग दृष्टिकोण लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। यह जनादेश केवल पहले के निर्णय को अलग करने के सामान्य प्रवेश द्वार के अधीन है या जहां पहले का निर्णय प्रति अशुद्धि है। इस संबंध में गोदरेज सारा ली लिमिटेड (सुप्रा) के मामले में भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के हाल के निर्णय का भी संदर्भ लिया जा सकता है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस मुद्दे पर विचार कर रहा था कि क्या राजस्व विभाग विपरीत रुख अपनाने का हकदार होगा, एक बार उसी मुद्दे पर अधिकरण के पूर्व निर्णय को राजस्व विभाग द्वारा चुनौती नहीं दी गई है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने उक्त निर्णय के अनुच्छेद 34 और 35 के तहत निम्नानुसार व्यवस्था दी है

"34. वर्तमान अपील पर निर्णय लेते समय, हम मुख्य रूप से 21 नवंबर, 2001 के ट्रिब्यूनल के निर्विवाद आदेश के चेहरे पर पुनरीक्षण प्राधिकरण द्वारा क्षेत्राधिकार ग्रहण करने के मुद्दे से चिंतित हैं, न कि ट्रिब्यूनल या पुनरीक्षण प्राधिकरण द्वारा दिए गए निर्णय के गुणों के साथ। प्रतिवादियों के चेहरे पर जो बात सामने आती है वह यह है कि ट्रिब्यूनल का पूर्वोक्त निर्णय, जिसे निर्धारण प्राधिकरण के आदेश में उद्धृत किया गया है, ने अंतिम रूप प्राप्त कर लिया है। एक बार जब मुद्दा अंतिम रूप से समाप्त हो जाता है, तो निर्णय राज्य, एक फोर्टियोरी, पुनरीक्षण प्राधिकरण को बाध्य करता है। ट्रिब्यूनल का निर्णय पुनरीक्षण प्राधिकरण को स्वीकार्य नहीं हो सकता है, लेकिन यह ऐसे प्राधिकरण को यह समझने के लिए कोई आधार प्रस्तुत नहीं कर सकता है कि यह या तो उसी से बाध्य नहीं है या इसका पालन करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे मामले में पहला परंतुक सक्रिय हो जाता है और पुनरीक्षण प्राधिकरण द्वारा शक्तियों के प्रयोग पर रोक के रूप में कार्य करेगा।

35. हमारे विचार में, पुनरीक्षण प्राधिकरण को निर्धारण प्राधिकरण के आदेश को संशोधित करने के लिए स्वतः प्रेरणा शक्ति का प्रयोग करने में उचित ठहराया जा सकता था, ट्रिब्यूनल के निर्णय को अलग रखा गया था या इसके संचालन को सक्षम न्यायालय द्वारा रोक दिया गया था। जब तक यह विवादित नहीं है कि ट्रिब्यूनल का निर्णय, उत्पादों/कर देयता के वर्गीकरण के ढांचे के संबंध में, तब तक मौजूद है, लागू रहना जारी है और ऐसा ढांचा भी लागू रहता है जब आक्षेपित पुनरीक्षण आदेश दिए गए थे, पुनरीक्षण प्राधिकरण के पास बिना किसी आरक्षण के ट्रिब्यूनल के निर्णय का पालन करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं बचा था। जब तक उच्च प्राधिकारियों द्वारा लिए गए निर्णयों का अनुपालन करने का अनुशासन नहीं रखा जाता है, तब तक कर निर्धारितियों को अनुचित रूप से परेशान करने के अलावा कर कानूनों के प्रशासन में घोर अव्यवस्था होगी। हम कमलाक्षी फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (सुप्रा) में व्यक्त किए गए विचारों से सहमत हैं।

36. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पूर्वोक्त आधिकारिक निर्णयों के मद्देनजर, हमारा दृढ़ मत है कि एक बार जब उत्तरदाताओं ने उसी मुद्दे पर मूल्यांकन प्राधिकारी द्वारा पारित मूल्यांकन आदेश पर विवाद नहीं किया है, तो उत्तरदाता-विभाग को कानून के तहत, विपरीत रुख अपनाने के लिए रोक दिया जाता है।

37. अब हम वाणिज्यिक कर न्यायाधिकरण, झारखंड के निष्कर्ष की वैधता और औचित्य की जांच कर सकते हैं, जिसमें ट्रिब्यूनल ने माना है कि याचिकाकर्ता और उपरोक्त दो संस्थाओं के बीच दर्ज किए गए समझौते भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 23 का उल्लंघन होने के कारण शून्य हैं, क्योंकि उक्त समझौते केवल कर का लाभ उठाने के प्रयोजनों के लिए दर्ज किए गए थे।

38. हमारा विचार है कि विद्वान ट्रिब्यूनल ने पूर्वोक्त निष्कर्ष देते हुए, स्पष्ट रूप से मामले के रिकॉर्ड से परे यात्रा की है और स्व-प्रेरणा से, एक निष्कर्ष दिया है जो इससे पहले राजस्व विभाग का मामला भी नहीं था।

39. इसके अलावा, यह एक निर्धारिती के लिए है कि वह अपने मामलों की कानूनी तरीके से योजना बनाए, जिसके परिणामस्वरूप कर की कम लेवीबिलिटी और/या कर

की कोई लेवीबिलिटी नहीं हो सकती है। जब तक किसी निर्धारिती द्वारा उठाए जा रहे इस तरह के कदम को भारत के कानून और/या सार्वजनिक नीति के खिलाफ घोषित नहीं किया जाता है, तब तक एक निर्धारिती से केवल इसलिए पूछताछ नहीं की जा सकती क्योंकि उसकी कर योजना के कारण उसे कर की कम राशि और/या कोई कर नहीं देना था।

**40. निर्गम सं. (2):** याचिकाकर्ता की कैंटीन बिक्री के संबंध में, राज्य के अधिवक्ता ने उचित रूप से प्रस्तुत किया है कि यदि याचिकाकर्ता के पास 82,36,603.74/- रुपये का बिक्री का अतिरिक्त प्रमाण पत्र है, तो आदेश पारित करने के चरण में मूल्यांकन प्राधिकारी द्वारा उस पर विचार किया जाएगा

**41.** उत्तरदाता-राज्य के अधिवक्ता के पूर्वोक्त निष्पक्ष प्रस्तुतिकरण के मद्देनजर, उक्त मुद्दा अब एकीकृत नहीं है और, इसके द्वारा यह आदेश दिया जाता है कि मूल्यांकन प्राधिकारी सीएसडी बिक्री से संबंधित बिक्री प्रमाण पत्र पर विचार करेगा 82,36,603.74 / -, जो याचिकाकर्ता द्वारा बाद में प्राप्त किया गया है और उक्त प्रमाण पत्र के अनुसार कर की आनुपातिक कटौती देगा।

**42.** याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी दलीलों के दौरान, इस तथ्य पर प्रकाश डाला कि इस न्यायालय द्वारा 21 दिसंबर, 2018 को पारित अंतरिम आदेश के अनुसरण में, याचिकाकर्ता ने आक्षेपित मांग के लिए 50.00 लाख रुपये जमा किए हैं और यह आदेश दिया गया था कि यदि याचिकाकर्ता तत्काल रिट आवेदन में सफल हो जाता है, तो यह न्यायालय वैधानिक ब्याज के साथ उसी राशि की वापसी के लिए आदेश पारित कर सकता है, जैसा कि बिहार वित्त अधिनियम, 1981 के तहत प्रदान किया गया है। इस संबंध में बिहार वित्त अधिनियम, 1981 की धारा 43 का संदर्भ लिया जाए जिसमें निर्धारिती को प्रतिदेय पाई गई राशि पर 9% सांविधिक ब्याज प्रदान करने का प्रावधान है। चूंकि वर्तमान मामले में, इस न्यायालय द्वारा पारित 21 दिसंबर, 2018 के अंतरिम आदेश के अनुसार याचिकाकर्ता द्वारा 50.00 लाख रुपये की राशि जमा की गई थी, इसलिए यह आदेश दिया जाता है कि जमा की तारीख से रिफंड

की तारीख तक 50.00 लाख रुपये की राशि ब्याज @ 6% प्रति वर्ष के साथ याचिकाकर्ता को तुरंत वापस कर दी जाए।

43. उपर्युक्त संचयी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, हम वाणिज्यिक कर न्यायाधिकरण, झारखंड द्वारा 13 अप्रैल, 2017 (अनुलग्नक-14) के आक्षेपित आदेश को रद्द करते हैं और रद्द करते हैं। (ख) दिनांक 16-12-2011 के पुनरीक्षण याचिका सं जेआर 02/2012 में पारित आदेश (अनुबंध-9) में भी दिनांक 16-12-2011 (अनुबंध-9) के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। (i) वाणिज्यिक कर अधिकरण, झारखंड द्वारा रिट याचिका सं जेआर 22/2006।

44. हम आगे उत्तरदाता नंबर 3-निर्धारण अधिकारी को निर्देश देते हैं कि वह याचिकाकर्ता द्वारा सैन्य कैंटीन स्टोर विभाग को छूट की बिक्री के संबंध में प्राप्त प्रमाण पत्र पर विचार करे, जो ट्रिब्यूनल के समक्ष संशोधन कार्यवाही की पेंडेंसी के दौरान याचिकाकर्ता द्वारा प्राप्त किया गया है और परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता को कर की आनुपातिक कटौती प्रदान करने के लिए। पूर्वोक्त अभ्यास में ब्याज @ 6% प्रति वर्ष के साथ 50.00 लाख रुपये की राशि की वापसी का अभ्यास आदेश की तारीख से 10 (दस) सप्ताह की अवधि के भीतर निर्धारण अधिकारी द्वारा पूरा किया जाना चाहिए।

45. तत्काल रिट आवेदन, तदनुसार, पूर्वोक्त निर्देशों और टिप्पणियों के साथ अनुमति दी जाती है। लंबित अंतर्वर्ती आवेदन, यदि कोई हो, का भी निपटान किया जाता है। हालांकि, लागत के रूप में कोई आदेश नहीं होगा।

**(रॉगून मुखोपाध्याय, न्याया०)**

**(दीपक रोशन, न्याया०.)**

झारखंड उच्च न्यायालय, रांची

दिनांकित- 11 /12/2023

अमरदीप /ए. एफ. आर

**यह अनुवाद (तलत परवीन), पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया।**